ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे उधारकर्ताओं की सेवा कौन करता है? पीएसबी या निजी बैंक?

पिछले तीन दशकों से, नई आर्थिक नीतियों के नाम पर, लगातार सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण, निजी क्षेत्र के बैंकों को प्रोत्साहन, ओपन टैप बैंकिंग लाइसेंस नीति, बैंकिंग नियमों के उदारीकरण, कमजोर करना, अगर विघटित नहीं नहीं तो सामाजिक बैंकिंग, कॉर्पोरेट चूककर्ताओं को रियायतें, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण को कमजोर करना, ग्रामीण ऋण का व्यावसायीकरण आदि जैसे बैंकिंग सुधार उपायों को आगे बढ़ा रही हैं और उनकी वकालत कर रही हैं। ।

निजी क्षेत्र के बैंकिंग के समर्थकों द्वारा बार-बार और सुनियोजित प्रचार किया जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कुशल नहीं हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग अब प्रासंगिक नहीं है, निजी बैंक लोगों की अधिक कुशलता से सेवा करते हैं, आदि।

राष्ट्रीयकृत बैंक - हमारी अर्थव्यवस्था के स्तंभ:

अर्थव्यवस्था और उसके विकास को व्यापक आधार देने के एक बहुत ही स्पष्ट सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य के साथ 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पिछले 50 से अधिक वर्षों में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एक दृश्यमान सामाजिक उन्मुख दिशा के साथ एक मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। 8000 शाखाएँ आज 86,000 बैंक शाखाएँ बन गई हैं, जिनमें से 42,000 शाखाएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं जो पहले नहीं थीं। प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण देने से हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है जिसके परिणामस्वरूप हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा, रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी आदि जैसी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं।

2008 में जब पूरा विश्व वित्तीय उथल-पुथल और बैंकिंग सुनामी का सामना कर रहा था, जहां दुनिया भर के निजी बैंक ताश के पत्तों की तरह ढह गए, हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वजह से भारतीय बैंकिंग प्रणाली सुरक्षित थी।

सरकार सबके साथ, सबका विकास चाहती है लेकिन समृद्धि के लिए जीवन रेखा को काटना चाहती है:

सरकार सभी के लिए प्रगति और समृद्धि की बात करती है लेकिन दुर्भाग्य से, वे बैंकों के निजीकरण की नीति पर चल रहे हैं जो गरीब लोगों और आम जनता की आर्थिक स्थिति में सुधार लेन वाली सरकारी योजनाओं और नीतियों में भाग लेने के लिए आगे कभी आगे नहीं आएंगे, विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों में होंगी। यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं जो आम लोगों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ खड़े थे और आज भी खड़े हैं।

उदाहरण के लिए, निम्न तालिका देखें (मार्च, 2020 के आंकड़ें)

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखाएं	1,46,811	
जिसमें से ग्रामीण शाखाओं की कुल संख्या	51,572	35 %
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ग्रामीण शाखाएं	28,843	56%
निजी क्षेत्र के बैंकों की ग्रामीण शाखाएं	6,907	13%

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण	105,18,812 cr	
जिसमें से ग्रामीण शाखाओं में दिए गए कुल ऋण	9,10,816 cr	
ग्रामीण शाखाओं में पीएसबी द्वारा दिए गए कुल ऋण	5,69,700 cr	63%
ग्रामीण शाखाओं में निजी बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण	1,48,297 cr	16%

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण - खातों की संख्या	27.25 cr	
जिसमें से ग्रामीण शाखाओं में ऋण खातों की संख्या	7.86 cr	
ग्रामीण शाखाओं में पीएसबी द्वारा कुल ऋण खाते	3.37 cr	43%
ग्रामीण शाखाओं में निजी बैंकों द्वारा ऋण खाते	2.57 cr	33%

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा छोटे उधारकर्ताओं को दिए गए कुल ऋण	9,23,831 cr	
जिसमें से ग्रामीण शाखाओं में दिया जाता है	3,50,947 cr	
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्रामीण शाखाओं में छोटे उधारकर्ताओं को दिया गया ऋण	1,80,401 cr	51%
निजी बैंकों द्वारा ग्रामीण शाखाओं में छोटे उधारकर्ताओं को दिया गया ऋण	68,205 cr	19%

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा छोटे उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण- खातों की संख्या	20.96 cr	
जिसमें से ग्रामीण शाखाओं में दिया जाता है	6.68 cr	
छोटे कर्जदारों के ग्रामीण शाखाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण खाते	2.60 cr	39%
ग्रामीण शाखाओं में निजी बैंक द्वारा ऋण खाते	2.43 cr	36%

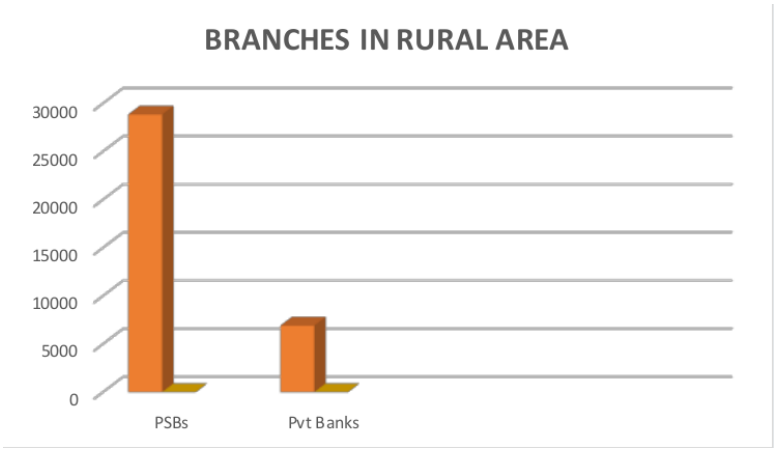
BRANCHES IN RURAL AREA
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
PSBs
Pvt Banks

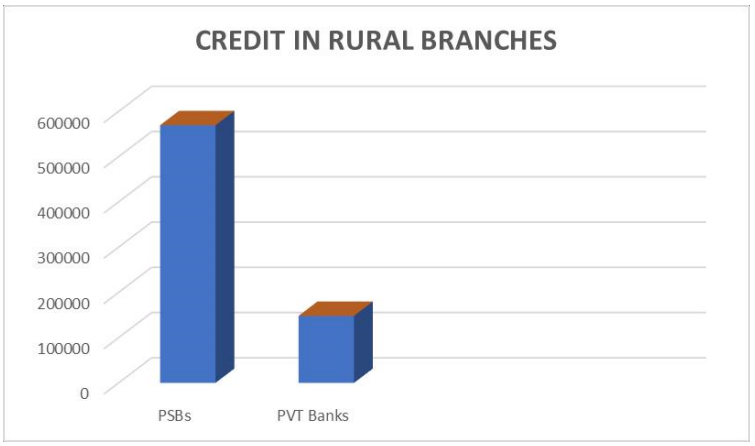
CREDIT IN RURAL BRANCHES
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
PSBs
PVT Banks

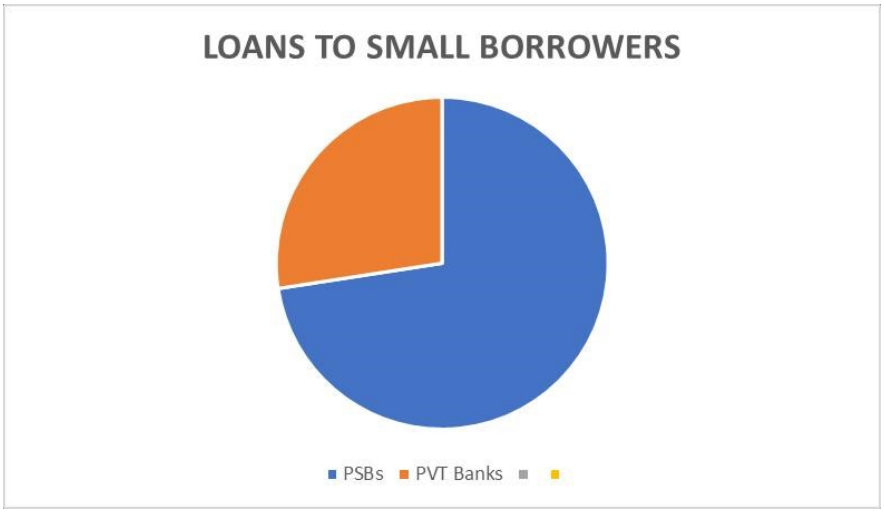
LOANS TO SMALL BORROWERS
PSBs
PVT Banks

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि निजी बैंकों (केवल 13%) की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं की संख्या (56%) अधिक है। यदि बैंकों का निजीकरण किया जाता है, तो इस ग्रामीण महत्त्व को शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और नुकसान होगा। क्या हम ऐसा होने दे सकते हैं?

इसी तरह, ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋणों में से, 63% ऋण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए जाते हैं जबकि ग्रामीण ऋण में निजी बैंकों की हिस्सेदारी केवल 16% है। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कौन अधिक सेवा करता है?

फिर से, जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में दिए गए ऋणों की तुलना छोटे उधारकर्ताओं से करते हैं, तो हम पाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उधारकर्ताओं को 51% ऋण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिया जाता है और निजी बैंकों का योगदान केवल 19% है।

बैंकों के निजीकरण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बचाने के लिए संघर्ष - निजीकरण के खिलाफ लड़ाई - ग्रामीण भारत को बचाएं